बनेंगे बड़े पैमाने पर ईवी चार्जिंग स्टेशन

नगर विकास विभाग ने ईवी चार्जिंग सुविधाओं के लिए उठाए कदम

स्मार्ट सिटी के तहत 17 नगर निगमों के लिए बनी कार्ययोजना

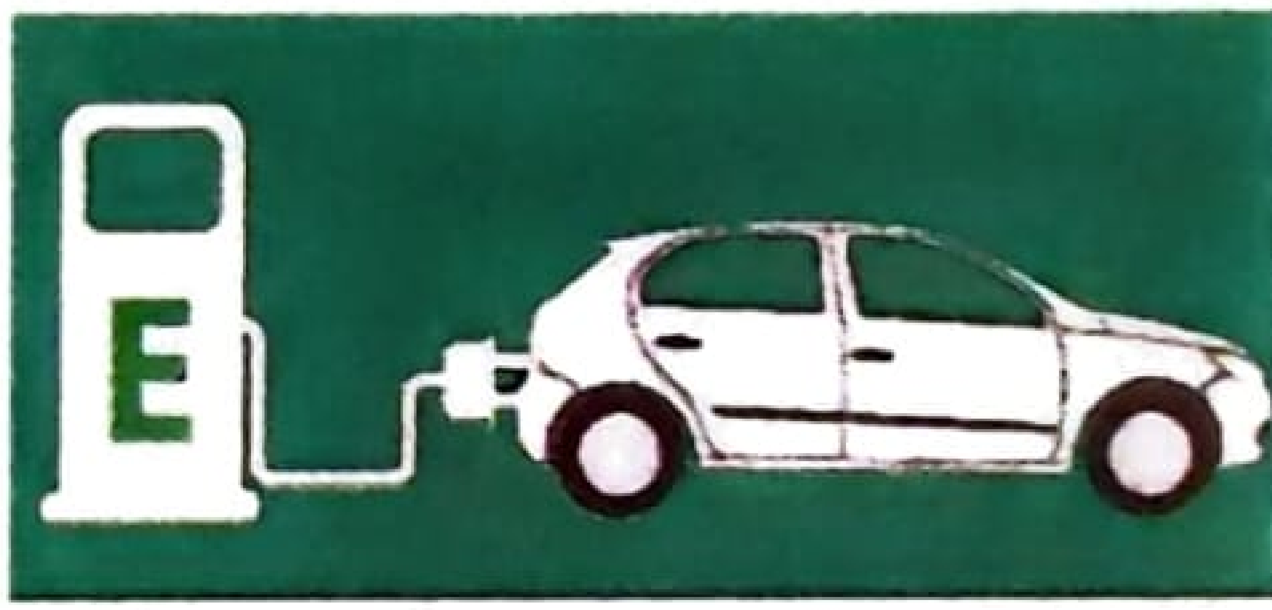

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : योगी सरकार ने प्रदेश में इलेक्ट्रिकल वीकल (ईवी) मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के साथ-साथ ईवी का इस्तेमाल कर रहे नागरिकों को चार्जिंग की पर्याप्त सुविधाएं देने की दिशा में गंभीर प्रयास शुरू किए हैं। ईवी चार्जिंग स्टेशन की स्थापना को लेकर नगर विकास विभाग ने सेवा प्रदाताओं की भूमि आवश्यकता की पूर्ति के साथ ही स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 17 नगर निगम के लिए कार्य योजना तैयार कर ली है। वहीं चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के फास्ट ट्रैक विकास के लिए नगर विकास विभाग के नेतृत्व में कार्यकारी समूह का भी गठन कर लिया गया है।

नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार ईवी नीति के अधीन नोडल संस्था इन्वेस्ट यूपी द्वारा स्वीकृत चार्जिंग स्टेशनों के लिए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ईवी नीति के अनुसार चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए सरकारी संस्थाओं को भूमि 10 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे या लीज पर उपलब्ध कराई जाएगी। चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए निजी संस्थाओं को भी भूमि समान रेवेन्यू शेयरिंग माडल के माध्यम से 10 वर्ष के लिए पट्टे पर प्रदान की जाएगी।

इलेक्ट्रिक वीकल मैन्यूफैक्चरिंग एवं मोबिलिटी पालिसी के मानकों के अनुरूप विभाग ने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के फास्ट ट्रैक विकास के लिए कार्यकारी समूह की स्थापना कर दी है। नगर विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव इसके अध्यक्ष होंगे, जबकि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव या सचिव, ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव या सचिव, परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव या सचिव, औद्योगिक विकास विभाग के प्रमुख सचिव या सचिव, स्थानीय निकाय निदेशालय के निदेशक, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, इन्वेस्ट यूपी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और नगर निगम लखनऊ के नगर आयुक्त सदस्य के रूप में समूह में शामिल किए गए हैं।

स्मार्ट सिटी मिशन से भी जुड़ेगी परियोजना

सरकार इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लान तैयार करने में नीति आयोग एवं एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ समन्वय कर रही है। योजना को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चयनित 17 नगर निगम वाले शहरों में विस्तारित किया जाएगा। एक पोर्टल भी विकसित किया जाएगा।